

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4496
27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत निधि आवंटन

†4496. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत आवंटित बजट का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में एससीएम के अंतर्गत चरण-वार चिह्नित शहरों के नाम क्या हैं;

(ग) बिहार के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत आवश्यक धनराशि आवंटित की गई है तथा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या उक्त चिह्नित शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्य समय पर पूरा होने की संभावना है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा उपर्युक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) 25.06.2015 को शुरू किया गया था। एससीएम के तहत शामिल 100 शहरों के लिए केंद्र सरकार का कुल परिव्यय 48,000 करोड़ रु. है। इस मिशन की शुरुआत से अब तक चयनित शहरों और उनके द्वारा दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

- (ख) से (ग) एससीएम के तहत बिहार राज्य से चार शहरों अर्थात फास्ट ट्रेक शहरों में भागलपुर, राउंड-2 में पटना और मुजफ्फरपुर तथा राउंड-3 में बिहारशरीफ का चयन किया गया है। ये शहर 1,735 करोड़ रु. की केंद्रीय वित्तीय सहायता का दावा कर पाए हैं, जिसमें से 1,669 करोड़ रु. (कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता का 96%) का उपयोग किया जा चुका है, जिसका शहर-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। दावा की गई और उपयोग की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का जिला-वार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।
- (घ) और (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों पर, भारत सरकार ने चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) को 31.03.2025 तक बढ़ा दिया है।
- (च) एससीएम के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। शहरी स्तर पर, विभिन्न हितधारकों के बीच सलाह देने और सहयोग को संभव बनाने के उद्देश्य से सभी 100 स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) की स्थापना का प्रावधान है ।

एससीएम के तहत निधि आवंटन के संबंध में 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4496 के भाग (क) का उत्तर

एससीएम के तहत चयनित शहरों द्वारा प्रारंभ से लेकर अब तक दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	245
पोर्ट ब्लेयर	245
आंध्र प्रदेश	1,984
अमरावती	560
काकीनाडा	490
तिरुपति	392
विशाखापत्तनम	542
अरुणाचल प्रदेश	978
ईटानगर	488
पासीघाट	490
असम	490
गुवाहाटी	490
बिहार	1,735
भागलपुर	490
बिहारशरीफ	376
मुजफ्फरपुर	442
पटना	427
चंडीगढ़	490
चंडीगढ़	490
छत्तीसगढ़	1,352
अटल नगर	488
बिलासपुर	429
रायपुर	435
दादरा और नागर हवेली	392
सिल्वासा	392
दमन और दीव	386
दीव	386
दिल्ली	343
एनडीएमसी	343

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
गोवा	441
पणजी	441
गुजरात	2,947
अहमदाबाद	490
दाहोद	417
गांधीनगर	490
राजकोट	490
सूरत	570
वडोदरा	490
हरियाणा	980
फरीदाबाद	490
करनाल	490
हिमाचल प्रदेश	978
धर्मशाला	490
शिमला	488
जम्मू और कश्मीर	856
जम्मू	440
श्रीनगर	416
झारखंड	490
रांची	490
कर्नाटक	3,507
बेलगावी	490
बेंगलुरु	488
दावनगेरे	490
हुबली, धारवाड़	606
मंगलुरु	453
शिवमोगा	490
तुमकुरु	490
केरल	993
कोच्चि	505
तिरुवनंतपुरम	488
लक्षद्वीप	183
कावारत्ती	183
मध्य प्रदेश	3,510
भोपाल	490
ग्वालियर	490
इंदौर	490

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
जबलपुर	490
सागर	490
सतना	490
उज्जैन	570
महाराष्ट्र	3,826
अमरावती #	2
औरंगाबाद	490
ग्रेटर मुंबई #	2
कल्याण-डोम्बीवली	490
नागपुर	453
नासिक	429
पिंपरी-चिंचवाड	490
पुणे	490
सोलापुर	490
ठाणे	490
मणिपुर	352
इंफाल	352
मेघालय	490
शिलांग	490
मिजोरम	490
आइजोल	490
नागालैंड	490
कोहिमा	490
ओडिशा	988
राउरकेला	490
भुवनेश्वर	498
पुदुचेरी	415
पुदुचेरी	415
पंजाब	1,527
अमृतसर	498
जालंधर	444
लुधियाना	490
सुल्तानपुर लोधी #	95
राजस्थान	1,960
अजमेर	490
जयपुर	490
कोटा	490

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
उदयपुर	490
सिक्किम	932
गंगटोक	488
नामची	444
तमिलनाडु	5,504
चेन्नई	602
कोयंबटूर	490
डिंडीगुल #	2
इरोड	490
मदुरै	490
सलेम	490
तंजावुर	490
थूथूकोडी	490
तिरुचिरापल्ली	490
तिरुनेलवेली	490
तिरुपूर	490
वेल्लोर	490
तेलंगाना	806
ग्रेटर वारंगल	377
करीमनगर	429
त्रिपुरा	541
अगरतला	541
उत्तर प्रदेश	4,906
आगरा	490
अलीगढ़	490
बरेली	490
गाजियाबाद #	2
झांसी	490
कानपुर	490
लखनऊ	490
मेरठ/रायबरेली #	2
मुरादाबाद	490
प्रयागराज	490
रामपुर #	2
सहारनपुर	490
वाराणसी	490
उत्तराखंड	536

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
देहरादून	536
पश्चिम बंगाल	496
बिधाननगर #	2
दुर्गापुर #	2
हल्दिया #	2
न्यू टाउन कोलकाता	490
कुल योग	47,538

4 मार्च 2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

टिप्पणी:

1. # का अर्थ है 'स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित नहीं हुआ शहर' (₹ 18 करोड़)
2. * सुल्तानपुर लोधी को निधियां (₹ 94.89 करोड़)
3. सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के लिए जारी निधियां (₹ 711.99 करोड़)

एससीएम के तहत निधि आवंटन के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4496 के भाग (ख) से (ग) का उत्तर

बिहार राज्य से एससीएम के अंतर्गत चयनित चार शहरों द्वारा दावा की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/शहर-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	शहर	राउंड	दावा की गई कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता	दावा की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का कुल उपयोग
1	भागलपुर	फास्ट ट्रैक	490	483
2	पटना	राउंड 3	376	342
3	मुजफ्फरपुर	राउंड 3	442	419
4	बिहारशरीफ	राउंड 4	427	425
		कुल	1,735	1,669

4 मार्च 2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।
